राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

खंडपीठ सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 245/2019

में

एकलपीठ सिविल रिट समीक्षा संख्या 269/2016

में

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 193/1999

धर्मपाल मोरया पुत्र श्री रामधन मोरया, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी ग्राम भांडारेज जिला दौसा (राजस्थान)

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. **रजिस्ट्रार**, कोटा मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा, क्षेत्रीय केंद्र, **जवाहर लाल नेहरू मार्ग**, जयपुर
2. **परीक्षा नियंत्रक, कोटा मुक्त विश्वविद्यालय**, कोटा
3. **निदेशक**, क्षेत्रीय केंद्र, **कोटा मुक्त विश्वविद्यालय**, कोटा, क्षेत्रीय केंद्र, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
4. **जिला शिक्षा अधिकारी**, दौसा, राजस्थान

---- प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी (गण) की ओर से : **श्री राजेंद्र कुमार सोनी** अधिवक्ता

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : **सुश्री अनिता अग्रवाल** अधिवक्ता **श्री अनुभव अग्रवाल** अधिवक्ता के साथ।

माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति विनोद कुमार भरवानी

निर्णय/आदेश

रिपोर्टेबल

01/11/2022

सुना।

यह अपील विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित दिनांक 16.12.2015 के आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी गई है।

अनावश्यक विवरणों से रहित, इस अपील को जन्म देने वाले मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स यह है कि अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता, बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने का इच्छुक है। जिसने प्रत्यर्थियों के संस्थान में अपने प्रत्यक्ष पक्षों के साथ आवेदन किया, जिसमें बी.कॉम उत्तीर्ण होने की डिग्री के साथ उसके वाणिज्य स्नातक होने की डिग्री और शिक्षण अनुभव का प्रमाणपत्र भी शामिल था। अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता को अनंतिम प्रवेश दिया गया था। उन्होंने बी.एड. पाठ्यक्रम की पढ़ाई जारी रखी और उसके बाद, अंतिम परीक्षा में उपस्थित हुए और न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने के बाद, उत्तीर्ण घोषित कर दिए गए। अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता के पक्ष में बी.एड उत्तीर्ण पाठ्यक्रम करने की एक मार्कशीट जारी किया गया था। हालाँकि, इसके बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी-संस्थान द्वारा अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता के विरूद्ध कुछ प्रतिकूल सामग्री एकत्र की गई थी, जिसके कारण दिनांक 16/17.09.1998 के आदेश के तहत उसका प्रवेश रद्द कर दिया गया था। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दायर की।

रिट याचिका में, प्रारंभ में विद्वान एकलपीठ ने 14.09.1999 को एक अंतरिम आदेश पारित किया था जिसमें परीक्षा रद्द किए जाने के आदेश के प्रवर्तन को स्थगित किया गया था। हालांकि, विश्वविद्यालय को जांच करने की स्वतंत्रता की गई थी। जब मामला 03.02.2014 को फिर से अदालत के सामने सुनवाई के लिए आया, तो रिट याचिका पर दबाव डालने वाला कोई नहीं था, इसलिए इसे खारिज कर दिया गया। हालाँकि, यह देखा गया कि यदि अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता ने पहले ही पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है तो रिट याचिका खारिज होने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्हें इस आदेश की जानकारी नहीं थी और जब विभागीय प्राधिकारी ने उन्हें 16.07.2015 को नोटिस दिया तब जाकर उन्हें इसके बारे में पता चला और इसलिए, बहाली के लिए एक आवेदन दायर किया गया। दिनांक 16.12.2015 के आदेश के द्वारा, दिनांक 03.02.2014 के आदेश को वापस ले लिया गया, रिट याचिका को उसकी मूल संख्या में बहाल कर दिया गया और उसी समय, विद्वान एकलपीठ ने रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रत्यर्थियों द्वारा दिए गए इस तर्क को खारिज नहीं कर सकते कि अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाणपत्र जाली था। यही वह आदेश है, जिस पर इस अपील में सवाल उठाया गया है।

अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जिस परीक्षा में अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता सफलतापूर्वक उपस्थित हुआ था और उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया था, उसे रद्द करना उसे सुनवाई का कोई भी अवसर दिए बिना किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि अनुभव प्रमाणपत्र फर्जी होने का आरोप गंभीर है। अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के साथ रिट याचिका के साथ संलग्न है और जिसे बी.एड पाठ्क्रम में प्रवेश के समय प्रवेश अधिकारियों के समक्ष भी रखा गया था। उनका तर्क था कि वह सामग्री, जो अपीलार्थी के पीठ पीछे प्रत्यर्थियों-अधिकारियों द्वारा परीक्षा रद्द करने के लिए उसके परीक्षा उत्तीर्ण करने के बहुत बाद एकत्र की गई थी, उसे कभी भी उसके सामने प्रकट नहीं किया गया था। अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का आगे का तर्क था कि अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता को उसकी परीक्षा रद्द करने की इतनी कठोर कार्रवाई करने से पहले सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था। अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तर्क दिया कि प्रत्यर्थियों-अधिकारियों की कार्रवाई के परिणामस्वरूप गंभीर सिविल परिणाम हुए हैं, इसलिए, प्रत्यर्थियों को सुनवाई का अवसर देना चाहिए था और इसी प्रकार प्रतिकूल सामग्री का भी खुलासा करना चाहिए था, जिसके आधार पर परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया था। यह तर्क दिया गया है कि ऐसा नहीं किया गया है, प्रत्यर्थियों-अधिकारियों की विवादित कार्रवाई विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण है।

सामानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क

दिया कि वर्तमान मामले में, जब अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता ने बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया था, उन्हें स्पष्ट शर्तों और अनुबंध पर केवल अनंतिम प्रवेश दिया गया था कि यदि, भविष्य में, कोई भी तथ्य या दस्तावेज़ गलत/सही नहीं पाया गया, तो प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा और शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। उत्तर में दिए गए कथनों का हवाला देते हुए, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सामान्य सत्यापन के अनुसार, अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता सहित विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाणपत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को भेजे गए थे, जहां से उन प्रमाणपत्रों प्राप्त किया गया था। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी यह थी कि अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाणपत्र जाली था। प्रत्यर्थियों के पास संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त आधिकारिक संचार की सत्यता या शुद्धता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था और इसलिए, उस आधार पर, अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता का प्रवेश रद्द कर दिया गया था।

प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता अपने भार का निर्वहन करके यह प्रमाणित करने और सिद्ध करने में विफल रहा है कि उसने वास्तव में उस अवधि के लिए स्कूल में पढ़ाया था जिसके संबंध में उसके पक्ष में प्रमाणपत्र जारी किया गया था और जिसके आधार पर, उन्होंने बी.एड पाठ्क्रम में प्रवेश पाया था। इस न्यायालय के समक्ष भी, यह तर्क दिया गया है कि संबंधित स्कूल के प्रासंगिक रिकॉर्ड यह सिद्ध करने और स्थापित करने के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं कि अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता ने वास्तव में संबंधित स्कूल में पढ़ाया है जिसके आधार पर वह अनुभव प्राप्त करने का पात्र था। इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का आधार पर अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता किसी राहत का पात्र नहीं है। अपनी दलील के समर्थन में, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने **राम सरन बनाम पुलिस महानिरीक्षक, सीआरपीएफ और अन्य, (2006) 2 उच्चतम न्यायालय मामले 541 और जयश्री बनाम निदेशक कॉलेजिएट शिक्षा, (सिविल अपील संख्या 1559 ऑफ़ 2022) ने 22.02.2022** के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया है।

प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि जब शुरू में 14.09.1999 को न्यायालय द्वारा रद्दीकरण के आदेश के संचालन पर रोक लगाने का आदेश पारित

किया गया था, तो जांच करने की स्वतंत्रता विश्वविद्यालय के लिए आरक्षित थी। विश्वविद्यालय ने अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया, लेकिन अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता ने यह कहकर उत्तर दिया कि मामला न्यायाधीन है। इसलिए, अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर विवेकाधीन राहत का पात्र नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि बाद में, अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता के नियोक्ता ने भी 16.07.2015 को नोटिस देने के बाद दिनांक 14.12.2015 के आदेश के तहत अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त कर दिया। उपरोक्त विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को एक अन्य रिट याचिका में अलग से चुनौती दी गई है, जहां तक वर्तमान अपील का संबंध है, अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता किसी भी राहत का पात्र नहीं है।

हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेखों का अवलोकन किया है और हमारे समक्ष प्रस्तुत विभिन्न निवेदनों पर उत्सुकतापूर्वक विचार किया है।

यह विवादित नहीं है कि प्रवेश के समय, अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता ने बी.एड पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए अपनी पात्रता के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। उनमें से एक तीन साल का शिक्षण अनुभव है। रिट याचिका के साथ, अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता ने दिनांक 23.12.1995 का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है, जिससे पता चलता है कि उन्होंने 01.07.1992 से 20.12.1995 तक सीनियर सेकेंडरी विश्वबंधु विद्या मंदिर, भंडारेज, जिला दौसा में लगातार पढ़ाया है। स्कूल को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भी घोषित किया गया है। इस प्रमाणपत्र पर न सिर्फ जिला शिक्षा पदाधिकारी, बल्कि संबंधित स्कूल के हेडमास्टर समेत कई अन्य अधिकारियों की मुहर और हस्ताक्षर हैं. अनुभव के उपरोक्त प्रमाणपत्र के आधार पर, अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता को बी.एड. पाठ्क्रम में प्रवेश के लिए पात्र माना गया। अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता को 16.04.1996 को एक प्रवेश पत्र जारी किया गया और उसके बाद 01.07.1996 को पत्र जारी किया गया। हालाँकि, पत्र में कहा गया है कि प्रवेश अनंतिम है, यह रिकॉर्ड पर एक निर्विवाद तथ्य है कि अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता को पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई थी, वह परीक्षा में शामिल हुआ और उसने सफलतापूर्वक बी.एड. पाठ्यक्रम भी उत्तीर्ण किया, जो रिट याचिका के साथ संलग्न उसकी मार्कशीट से स्पष्ट है। परीक्षा दिसंबर, 1997 में

आयोजित की गई थी। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि शुरू में प्रवेश को अनंतिम माना गया था, समय बीतने के साथ, अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता को पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई, परीक्षा में उपस्थित हुआ और उत्तीर्ण भी घोषित किया गया, इसलिए, उसका प्रवेश प्रकृति में अनंतिम माना जा सकता है। अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता ने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने का अधिकार हासिल कर लिया और सफलतापूर्वक पूरा करने पर उसे डिग्री भी प्रदान की गई।

अंततः 17.09.1998 को आक्षेपित आदेश द्वारा दिसंबर, 1997 में आयोजित बी.एड. पाठ्क्रम का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया, जिसमें अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता सहित कई उम्मीदवारों का परिणाम रद्द कर दिया गया था।

इसमें कोई विवाद नहीं है कि दिसंबर, 1997 में आयोजित परीक्षा के आधार पर परिणाम रद्द करने से पहले अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था। यह अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता के विरूद्ध एक गंभीर कार्रवाई थी, जिसने न केवल उसके शैक्षणिक कैरियर को प्रभावित किया, बल्कि रोजगार की भविष्य की संभावनाओं को भी प्रभावित किया। इस तरह के गंभीर परिणाम होने के कारण, यह एक ऐसा मामला था जहां अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता को कार्रवाई करने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था।

हमने यह भी देखा है कि जब रिट याचिका में 14.09.1999 को अंतरिम आदेश पारित किया गया था, तो जांच करने की स्वतंत्रता विश्वविद्यालय के लिए आरक्षित थी और अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता को भी नोटिस दिया गया था, जिसका उत्तर अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया था, लेकिन उसके बाद, विश्वविद्यालय मामले में अंतिम आदेश पारित करने के लिए आगे नहीं बढ़ा।

वर्तमान अपील में सुनवाई के दौरान, 13.12.2021 को हमारे सामने एक बयान दिया गया था कि बाद में वर्ष 2015 में एक और जांच की गई थी जिसमें अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया गया था। इसके बाद, प्रत्यर्थियों द्वारा हलफनामा दायर किया गया है जो केवल यह दर्शाता है कि एक नोटिस दिया गया था, उत्तर प्राप्त किया गया था, लेकिन उसके बाद, कुछ भी नहीं हुआ, यहां तक कि अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता के विरूद्ध कोई आदेश भी पारित नहीं किया गया।

कुछ अपवादों के अधीन, यह एक अच्छी तरह से स्थापित कानूनी प्रस्ताव है जैसा कि **मोहिंदर सिंह गिल और अन्य बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य, एआईआर 1978 उच्चतम न्यायालय 851** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी संविधान पीठ के निर्णय में कहा था, जब भी प्रतिकूल सिविल परिणाम सामने आते हैं, सुनवाई का अवसर और आमतौर पर यह किसी भी बहिष्करणीय नियम को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए, कोई भी प्रतिकूल कार्रवाई करने से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान करना केवल कुछ अपवादों के अधीन सामान्य अनुप्रयोग का सिद्धांत है।

इस अदालत को यह समझाने के लिए कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुप्रयोग के लिए एक अपवाद का मामला है, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता ने अदालत से संपर्क किया था और उसे उचित साक्ष्य, मौखिक और/या दस्तावेज़ों द्वारा यह स्थापित करना आवश्यक था कि अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता ने विवादित प्रमाणपत्र में बताई गई अवधि के लिए वास्तव में संबंधित स्कूल में पढ़ाया था।

हम इस तर्क से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं. संबंधित स्कूल के रिकॉर्ड अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता के हाथ में नहीं हैं। वह उन अभिलेखों का संरक्षक नहीं है। दूसरे, यह मुद्दा कि प्रमाणपत्र जाली था या नहीं, केवल तथ्यान्वेषी जांच में ही तय किया जा सकता है। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि जिस प्रमाणपत्र को विवादित मानने की कोशिश की गई है, उस पर न केवल जिला शिक्षा अधिकारी ने अपनी मुहर के साथ हस्ताक्षर किए हैं, बल्कि उस स्कूल के हेडमास्टर ने भी हस्ताक्षर किए हैं, जहां अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने विभिन्न कक्षाओं को पढ़ाया है। प्रत्यर्थी-संस्था द्वारा और न ही जिला शिक्षा अधिकारी, जिला दौसा द्वारा, जो इस अपील में एक पक्ष भी है, न्यायालय के समक्ष कोई सामग्री नहीं रखी गई ताकि न्यायालय को यह विश्वास दिलाया जा सके कि वर्तमान मामले में यह पूर्वविदित निष्कर्ष है और सुनवाई का अवसर देना बेकार औपचारिकता होगा। हमारे सामने रखी गई ऐसी किसी भी सामग्री के अभाव में, अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता को अन्यथा सिद्ध करने की आवश्यकता होगी, यह कानून के स्थापित सिद्धांतों को पूरी तरह से खारिज करने जैसा होगा कि सुनवाई का अवसर दिए बिना सिविल परिणामों के परिणामस्वरूप होने वाली कार्रवाई शून्यकरणीयता

होगी। सार्वजनिक प्राधिकारियों की कार्रवाई को प्राकृतिक न्याय, न्यायसंगतता और निष्पक्षता के सिद्धांतों की पुष्टि करनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को वर्तमान की तरह गंभीर प्रकृति के सिविल परिणामों का सामना करना पड़ता है, तो अन्यथा सिद्ध करने के लिए उस व्यक्ति पर उल्टा बोझ नहीं डाला जा सकता है, भले ही जिन आरोपों के आधार पर उसके विरूद्ध कार्रवाई की गई है, न्यायालय के समक्ष उन्हें सिद्ध नहीं किया जा सके। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किए गए संचार को छोड़कर, हमारे सामने किसी ठोस सामग्री के अभाव में, हम यह मानने के इच्छुक नहीं हैं कि वर्तमान मामला कोई अपवाद का मामला है।

किन असाधारण परिस्थितियों में, केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किसी पक्ष को राहत का पात्र नहीं बना देगा, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कई मामलों में इस पर विचार किया गया है।

<u>अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और अन्य बनाम मंसूर अली खान, (2000) 7 उच्चतम न्यायालय केस 529</u> के मामले में, उच्चतम न्यायालय माननीय न्यायधीश ने आधिकारिक रूप से माना कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन न करना जब तक कि मामले का पूर्वाग्रह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत स्वयमेव रूप से किसी को राहत का पात्र न बना दे। हालाँकि, माननीय न्यायधीश ने बेकार औपचारिकता के सिद्धांत को निम्नानुसार समझाया:-

> “21. जैसा कि हाल ही में एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ 1999 (6) एससीसी 237 में बताया गया है। ऐसी कुछ स्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन में पारित आदेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, जहां संबंधित व्यक्ति पर कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है, वहां अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार, यदि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करने वाले आदेश को रद्द करने से एक अन्य आदेश के पुनरुद्धार की संभावना है जो अपने आप में अवैध है, जैसा कि गड्डे वेंकटेश्वर राव बनाम आ.प्र. सरकार ए.पी. एआईआर 1966 एससी 828 में है, के अनुसार, केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों

के उल्लंघन के कारण आदेश को रद्द करना आवश्यक नहीं है।

22. एम.सी. मेहता 1999 (6) एससीसी 237 में बताया गया था कि एक समय में, रिज बनाम बाल्डविन 1964 एसी 40 में यह माना गया था कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन अपने आप में पूर्वाग्रह के रूप में माना जाता था और किसी अन्य "वास्तविक" पूर्वाग्रह की आवश्यकता नहीं थी जिसे सिद्ध किया जाना है। लेकिन, तब से न केवल इंग्लैंड में बल्कि हमारे देश में भी नियम की कठोरता में ढील दी गई है। एस.एल. कपूर बनाम जगमोहन (1980) 4 एससीसी 379, चिन्नप्पा रेड्डी, जे. में रिज बनाम बाल्डविन 1964 एसी 40 का पालन किया और इस तर्क को खारिज करते हुए नई दिल्ली मेट्रोपॉलिटन कमेटी के सुपरसेशन के आदेश को रद्द कर दिया कि कोई पूर्वाग्रह नहीं था, हालांकि नोटिस नहीं दिया गया था। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर कार्यवाही रद्द कर दी गई। लेकिन उस मामले में भी कुछ अपवाद निर्धारित किए गए थे जिनका हम वर्तमान में उल्लेख करेंगे।

23. चिन्नप्पा रेड्डी, जे. एस.एल. कपूर केस (1980) 4 एससीसी 379 में दो अपवाद निर्धारित किए (एससीसी पृष्ठ 395 पर) अर्थात्, "यदि स्वीकृत या निर्विवाद तथ्यों पर केवल एक निष्कर्ष संभव था", तो ऐसे मामले में, सिद्धांत यह है कि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन स्वयं पूर्वाग्रह था लागू नहीं होगा। दूसरे शब्दों में यदि स्वीकृत या निर्विवाद तथ्यों पर कोई अन्य निष्कर्ष संभव नहीं था, तो प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करते हुए पारित आदेश को रद्द करना आवश्यक नहीं है। बेशक, यह एक अपवाद है, इस अपवाद को लागू करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।

24. यह सिद्धांत कि प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के अलावा, पूर्वाग्रह को भी सिद्ध किया जाना चाहिए, कई मामलों में विकसित किया गया है। के.एल. में त्रिपाठी बनाम भारतीय स्टेट बैंक (1984) 1 एससीसी 43, सब्यसाची मुखर्जी, जे. (जैसा कि वह तब थे) ने यह सिद्धांत भी दिया

कि न केवल प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है बल्कि वास्तविक पूर्वाग्रह (नोटिस जारी न करने के अलावा) सिद्ध करना पड़ा. वेड के प्रशासनिक कानून (5वां संस्करण, पृ.472-75) को उद्धृत करते हुए यह देखा गया: (एससीसी पृ.58, पैरा 31)

> " प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत कब लागू होंगे, न ही उनके दायरे और सीमा के बारे में कठोर नियम बनाना संभव नहीं है। ....शिकायतकर्ता के प्रति कुछ वास्तविक पूर्वाग्रह भी रहा होगा; प्राकृतिक न्याय के केवल तकनीकी उल्लंघन जैसी कोई चीज़ नहीं है। प्राकृतिक न्याय की आवश्यकताएं मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, जांच की प्रकृति, उन नियमों पर निर्भर होनी चाहिए जिनके तहत न्यायाधिकरण कार्य कर रहा है, जिस विषय-वस्तु पर विचार किया जाना है, इत्यादि।

तब से, इस न्यायालय ने कई मामलों में पूर्वाग्रह के सिद्धांत को लगातार लागू किया है। उपरोक्त निर्णय और समान दृष्टिकोण वाले विभिन्न अन्य निर्णयों को स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम एस.के. शर्मा (1996) 3 एससीसी 364 में विस्तृत रूप से संदर्भित किया गया है। उस मामले में, "पूर्वाग्रह" के सिद्धांत को और अधिक विस्तृत किया गया है। राजेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश सरकार (1996) 5 एससीसी 460 में भी यही सिद्धांत पुनः दोहराया गया है।

25. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि "निरर्थक औपचारिकता" सिद्धांत एक अपवाद है। ऊपर उल्लिखित "केवल एक निष्कर्ष पर पहुंचने वाले स्वीकृत या निर्विवाद तथ्यों" के मामलों की श्रेणी के अलावा, अन्य मामलों में उस सिद्धांत के अनुप्रयोग पर काफी बहस हुई है। ऊपर उल्लिखित इस सिद्धांत के संबंध में व्यक्त किए गए भिन्न विचारों पर इस न्यायालय द्वारा एम.सी. मेहता (1999) 6 एससीसी 237 में विस्तृत रूप से विचार किया गया है। इस न्यायालय ने इंग्लैंड में लॉर्ड रीड, लॉर्ड विल्बरफोर्स, लॉर्ड वूल्फ, लॉर्ड बिंघम, मेगारी, जे. और स्ट्रॉटन एल.जे.

आदि द्वारा विभिन्न निर्णयों में व्यक्त किए गए विचारों का सर्वेक्षण किया। विभिन्न मामलों में और प्रोफेसर जैसे प्रमुख लेखकों गार्नर, क्रेग, डी स्मिथ, वेड, डी.एच. क्लार्क आदि द्वारा व्यक्त विचारों में थी, उनमें से कुछ ने कहा है कि उल्लंघन में पारित आदेशों को हमेशा रद्द कर दिया जाना चाहिए अन्यथा न्यायालय इस मुद्दे पर पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाएगा। कुछ अन्य लोगों ने कहा है कि ऐसा कोई पूर्ण नियम नहीं है और पूर्वाग्रह अवश्य दिखाया जाना चाहिए। फिर भी, कुछ अन्य लोगों ने मीडिया नियमों के माध्यम से लागू किया है। ऐसे में हम इन मुद्दों की गहराई में जाना जरूरी नहीं समझते। अंतिम विश्लेषण में, यह किसी विशेष मामले के तथ्यों पर निर्भर हो सकता है।

उपरोक्त निर्णयों और विभिन्न परिस्थितियों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का सर्वेक्षण करने के बाद, उन सिद्धांतों को वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में लागू करने के बाद, हमारा विचार है कि वर्तमान पूर्व निश्चित निष्कर्ष निरर्थक औपचारिकता का मामला नहीं है। इसलिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप प्रत्यर्थियों की कार्रवाई शुरू से ही शून्य हो जाएगी, जैसा कि **मोहिंदर सिंह गिल (सुप्रा.)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने संवैधानिक पीठ के निर्णय में कहा था।

हालाँकि, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के लिए विभागीय प्राधिकारी द्वारा 14.12.2015 को पारित एक आदेश पर भरोसा किया है, हम पाते हैं कि उस जांच का दायरा केवल यह था कि क्या अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता के पास बी.एड. 1999 से 2014 की अवधि के बीच प्रमाणपत्र था। दिनांक 16.07.2015 का कारण बताओ नोटिस और दिनांक 14.12.2015 कर आदेश यह नहीं दर्शाता है कि अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देकर कोई साक्ष्य एकत्र किया गया था और फिर अनुभव प्रमाणपत्र फर्जी होने के संबंध में एक निष्कर्ष दर्ज किया गया था इसलिए, विभागीय कार्यवाही और दिनांक 14.12.2015 का आदेश भी अपने आप में यह बताने के लिए सामग्री नियत नहीं करता है कि वर्तमान असाधारण प्रकृति का मामला है ताकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आवेदन को बाहर रखा जा सके और

केवल उस आधार पर राहत से इनकार किया जा सके।

प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने **राम शरण बनाम पुलिस महानिरीक्षक, सीआरपीएफ और अन्य (सुप्रा.)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया है। यह एक ऐसा मामला था जहां भर्ती के समय दोषी कर्मचारी ने जन्मतिथि का प्रमाणपत्र जमा किया था, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी जन्मतिथि घोषित की गई तारीख से अलग थी। इसी आरोप में उनके विरूद्ध विभागीय जांच शुरू की गई, जिसके परिणामस्वरूप शुरू में पद में अवनति हुई, लेकिन अंततः सेवा से बर्खास्तगी हुई। अपील में भी उस आदेश की पुष्टि की गई। उच्च न्यायालय ने संबंधित सेवा नियमों के नियम 29 (डी) में निहित प्रावधानों पर विचार करते हुए पाया कि संबंधित प्राधिकारी के पास सजा बढ़ाने की शक्ति थी। चूंकि, उस मामले में अपीलार्थी गलत जन्मतिथि के आधार पर सेवा में आया था, याचिका पर विचार नहीं किया गया और यह पाया गया कि वह ग्रेच्युटी और अन्य लाभों का पात्र नहीं था।

जब मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लाया गया, तो यह आग्रह किया गया कि कर्मचारी सुदूर ग्रामीण इलाके का एक गरीब युवा था, अपीलार्थी की उम्र अपेक्षित उम्र से केवल दो महीने कम थी; उन्होंने लगभग 28 वर्षों तक सेवा की, जब वे सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले थे, तो कार्यवाही शुरू की गई। सज़ा की मात्रा को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। इसके उत्तर में उच्चतम न्यायालय में माननीय न्यायाधीश ने माना कि न्यायालय को प्रशासक के निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि वह अतार्किक न हो या प्रक्रियात्मक अनौचित्य से ग्रस्त न हो या न्यायालय की अंतरात्मा को चौंकाने वाला न हो, इस अर्थ में कि यह तर्क की अवहेलना है। या नैतिक मानक और इसके अलावा न्यायालय प्रशासक द्वारा चुने गए विकल्प की शुद्धता पर विचार नहीं करेगा और न्यायालय को अपने निर्णय को प्रशासक के निर्णय से प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए क्योंकि न्यायिक समीक्षा का दायरा निर्णय लेने की प्रक्रिया में कमी तक ही सीमित है न कि स्वयं निर्णय पर।

इस तरह के एक मुद्दे की जांच करते समय, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **आर. विश्वनाथ पिल्लई बनाम केरल राज्य और अन्य, (2004) 2 उच्चतम न्यायालय मामले 105** के मामले में निर्णय पर विचार किया कि क्या होगा एक उचित और आनुपातिक

जुर्माना, हालांकि यह एक गलत जाति प्रमाणपत्र का मामला था, इसके तहत निर्दिष्ट तर्क का प्रयोग किया गया था। उपरोक्त निर्णय, प्रत्यर्थियों के तर्क को आगे नहीं बढ़ाता है। यह एक ऐसा मामला था जहां माननीय उच्चतम न्यायालय का विचार मुख्य रूप से दंड के पहलू पर था और यह पाया गया कि व्यक्ति ने जन्मतिथि का गलत प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था, उसके पक्ष में कोई न्यायसंगत विचार नहीं किया गया था। वह निर्णय इस प्रतिपादन के लिए प्राधिकारी नहीं है कि जहां आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, वहां जांच को समाप्त किया जा सकता है या ऐसे मामलों में सुनवाई का अवसर नहीं दिया जा सकता है।

जयश्री बनाम निदेशक कॉलेजिएट शिक्षा (सुप्रा.) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय समान रूप से प्रत्यर्थियों के मामले में मदद नहीं करता है। वह अनुसूचित जनजाति के रूप में लाभ लेने से संबंधित मामला था, जिसका अपीलार्थी-कर्मचारी पात्र नहीं पाया गया। एक बार जब संबंधित अपीलार्थी-कर्मचारी द्वारा जाति की स्थिति पर विवाद नहीं किया जा सका, तो उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की थी कि बर्खास्तगी के आदेश से पहले कर्मचारी को एक अवसर देना व्यर्थ था। यह इस पृष्ठभूमि में था कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक अपवाद बनाया गया था जिसमें कहा गया था कि यह आरक्षित पद के विरूद्ध रोजगार प्राप्त करने का मामला है और कर्मचारी कथित श्रेणी से संबंधित नहीं है, सेवा समाप्ति की सुनवाई के अवसर से पहले की आवश्यकता नहीं है .

इसलिए, तथ्यों के आधार पर, उपरोक्त निर्णय भी लागू नहीं होता है और स्पष्ट रूप से अलग-अलग है।

परिणामस्वरूप, हमारा विचार है कि अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना उसकी परीक्षा रद्द करना शुरू से ही शून्य था और इसे कानून द्वारा बरकरार नहीं रखा जा सकता है, जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया है, हमारे निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, विद्वान एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया गया है। अपील कायम है मंजूर।

हम स्पष्ट करते हैं कि अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता की बी.एड. डिग्री और मार्कशीट को पुनर्जीवित किया जाता है।

मामला वर्ष 1999 का है। हालांकि सामान्य तौर पर हम मामले को समाप्त कर

देते, लेकिन यह ध्यान में रखते हुए कि आरोप जाली प्रमाणपत्र बनाने का है, इसकी जांच होनी चाहिए। तदनुसार, हम प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 और 3 को अपीलार्थी-रिट-याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद जांच करने और कानून के तहत उचित आदेश पारित करने की स्वतंत्रता देते हैं।

हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि जब तक तीन महीने की अवधि के भीतर जांच नहीं खोली जाती, तब तक उपरोक्त प्रत्यर्थियों के लिए किसी भी जांच को फिर से खोलना संभव नहीं होगा। जांच शुरू होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

(विनोद कुमार भरवानी), न्यायमूर्ति **(मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव), न्यायमूर्ति**

Sanjay Kumawat-42

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।
अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।